नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति छात्र

69. **श्री अजीत जोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति समुदाय के कितने प्रतिशत छात्रों को अब तक प्रवेश दिया गया है;

(ख) क्या उनका यह प्रतिशत इस संबंध में उनके लिए निर्धारित किये गये प्रतिशत से अधिक है या कम है, और यह कितना कम या अधिक है; और

(ग) नवोदय विद्यालयों में इन वर्गों के शिक्षकों और छात्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में **शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही)** : (क) और (ख) इस योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में परिकल्पित किया गया है बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो। यदि इन वर्गों में से किसी एक वर्ग के पर्याप्त संख्या में बच्चे अर्हक नहीं होते तो दोनों वर्गों के बीच में स्थानों का पारस्परिक अदला-बदली करना सम्भव होगा। परीक्षण प्रणालियों में आवश्यक कामचलाऊ प्रबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे उनके निर्धारित किए गए आरक्षणों के अनुसार नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :-

वर्ष	दाखिले के लिए प्रविष्ट/चुने गए छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
1986-87	5804	1166	20	662	11
1987-88	13804	2360	17	1602	12

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिशतता क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15% तथा $7\frac{1}{2}$% के राष्ट्रीय औसत से ज़रा अधिक है।

(ग) नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्तियां पहली बार ही मात्र प्रतिनियुक्ति आधार पर की जा रही हैं। इस बारे में शिक्षकों तथा छात्रों के लिए प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सरकार के विद्यमान आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

दूर-दराज के तथा आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टरों की तैनाती

70. **श्री अजीत जोगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों के बावजूद देश के दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टरों के पद या तो रिक्त पड़े हैं या वे डाक्टर अन्यत्र स्थानों से सम्बद्ध कर दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप वहां रहे

गरीब आदिवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं;

(ख) क्या सरकार आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए उनकी सेवा के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में उनके द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए कार्य किया जाना अनिवार्य करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उच्चतर माध्यमिक के तीन वर्षीय आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम को चलाने के लिए आयुर्विज्ञान विद्यालय खोलने का विचार रखती है ताकि कम से कम उन कम प्रशिक्षित डाक्टरों को इन क्षेत्रों में भेजा जा सके, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार अन्य कौन से कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार आदिवासी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के 22451 स्वीकृत पदों में से 2872 पद 31.3.1988 को खाली पड़े थे।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नही है।

(ग) जी नहीं। चिकित्सा शिक्षा पुनिरीक्षण समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत की थी, ने यह विचार व्यक्त किया था कि कोई इन्टरमीडियेट कोर्स चलाने या एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की वर्तमान अवधि को घटाने का कोई आधार नहीं है।

(घ) ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में रिक्तियों की मौजूदा दर 12.5 प्रतिशत है जो कि साधारणत. प्रोन्नति, स्थानांतरण त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति आदि के कारण किसी भी संवर्ग में अपेक्षित है।

Voluntary Agencies imparting Adult Education

71. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seven hundred voluntary agencies would be provided financial assistance for imparting functional literacy and adult education during the current financial year;

(b) if so, what is the number of voluntary agencies which were functioning and provided loan during 1987-88;

(c) if so, whether it has also come to Government's notice that voluntary agencies have not been helpful for imparting functional literacy and adult education; and

(d) if so, what were the voluntary agencies which were sacked because of non-utilisation and misuse of the funds?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) A target of involving 700 Voluntary Agencies (including the Voluntary Agencies assisted during 1987-88) in the National Literacy Mission has been fixed by Government for 1988-89.

(b) During 1987-88 301 voluntary agencies were sanctioned grants for taking up functional literacy projects.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise, since the performance of Voluntary Agencies assisted in 1987-88 has not yet been evaluated.